गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 230
दि. 21.12.2025,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

हर घर स्वदेशी
घर-घर स्वदेशी

सत्यमेव जयते
गुजरात सरकार

अटल नेतृत्व
अविरत विकास

गाँव-गाँव
लखपति दीदी और ड्रोन दीदी
महिला सशक्तिकरण की नई सदी

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री भूपेन्द्रभाई पटेल
माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात

"महिला सशक्तिकरण की दिशा में लखपति दीदी एक निर्णायक भूमिका निभाएंगी।" -श्री हर्ष संघवी, माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात

बंगाल में जंगलराज का आरोप, ममता सरकार पर पीएम मोदी का तीखा और व्यापक हमला

नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति और वहां की मौजूदा स्थिति को लेकर एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने नदिया जिले में प्रत्यक्ष रूप से रैली न कर पाने पर खेद जताते हुए कहा कि यह क्षेत्र भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भूमि श्री चैतन्य महाप्रभु से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि वह रानाघाट में कई अहम मुद्दे उठाना चाहते थे, लेकिन खराब मौसम के कारण व्यक्तिगत रूप से रैली में शामिल नहीं हो सके। इसके बावजूद उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता तक अपना संदेश स्पष्ट शब्दों में पहुंचाया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नदिया केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, सेवा और भक्ति की परंपरा का प्रतीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु की यह भूमि दूसरों की सेवा और मानवता के कल्याण के लिए जानी जाती रही है, और यही भावना मतुआ समाज के भाइयों और बहनों में आज भी दिखाई देती है। पीएम मोदी ने कहा कि नदिया और पूरे पश्चिम बंगाल के विकास के लिए काम करना उनके लिए सौभाग्य की बात है और उनकी सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है।

प्रधानमंत्री ने दावा किया कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों को सशक्त बनाने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है। उन्होंने बताया कि

राज्य में 52 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार का लक्ष्य हर गरीब को पक्का घर देना है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के एक करोड़ से अधिक परिवारों को नल से जल की सुविधा मिली है। उन्होंने कहा कि यदि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो विकास की रफ्तार और तेज होगी और योजनाओं का लाभ कहीं अधिक लोगों तक पहुंचेगा। स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि राज्य में 13 हजार से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं और 750 से अधिक पीएम-भाजपा केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर सीधा हमला करते हुए कहा कि जिस तरह बिहार की जनता ने बार-बार जंगलराज को नकारा है, उसी तरह अब पश्चिम बंगाल को भी टीएमसी के 'महा जंगलराज' से मुक्त होने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा गति और पैमाने पर विश्वास करती है, सुशासन को प्राथमिकता देती है, जबकि टीएमसी केवल कट और कमीशन की राजनीति में उलझी हुई है। प्रधानमंत्री का आरोप था कि आवास, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों से जुड़ी हजारों करोड़ रुपये की योजनाएं टीएमसी के असहयोग के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।

प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया कि यदि टीएमसी को मोदी या भाजपा का विरोध करना है तो वह बार-बार कर सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के विकास को रोकने का क्या औचित्य है। उन्होंने कहा कि टीएमसी की राजनीति पूरी तरह स्वार्थ से प्रेरित है और इसमें जनता के हितों के लिए कोई स्थान नहीं है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने हाल के वर्षों में बहुत कुछ सहा है और खासकर राज्य की नारी शक्ति की स्थिति बेहद चिंताजनक है।

प्रधानमंत्री ने हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि फुटबॉल प्रेमी राज्य पश्चिम बंगाल को टीएमसी के शासन में शर्मसार होना पड़ा है, जिससे युवाओं का मनोबल टूटा है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी अवैध घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, जबकि यही घुसपैठिये राज्य के गरीबों को लूटते हैं, आतंक और अराजकता फैलाते हैं और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करते हैं। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता से वादा किया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने मतुआ और नामाशूद्र समुदायों को विशेष रूप से संबोधित करते हुए कहा कि वे टीएमसी की दया पर नहीं हैं। नागरिकता संशोधन कानून के कारण उन्हें भारत में सम्मान के साथ रहने का अधिकार मिला है और भाजपा सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद इन समुदायों के कल्याण के लिए और भी बड़े कदम उठाए जाएंगे। अपने पूरे संदेश में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य पश्चिम बंगाल को भय, अराजकता और कथित जंगलराज से मुक्त कर विकास, सुरक्षा और सम्मान की राह पर आगे ले जाना है।

पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत, बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में आधे पद आरक्षित कर केंद्र सरकार ने खोला अवसरों का नया द्वार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत सेवा दे चुके युवाओं को बड़ी राहत देते हुए सीमा सुरक्षा बल में उनके लिए रोजगार के अवसरों को और मजबूत कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबल पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर सीधे 50 प्रतिशत कर दिया है। इस संबंध में बीएसएफ सामान्य ड्यूटी कैडर (गैर-गजटेड) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन करते हुए गजट अधिसूचना जारी की गई है। इस फैसले को अग्निवीर योजना के बाद भविष्य को लेकर चिंतित युवाओं के लिए एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है।

जारी अधिसूचना के अनुसार अब बीएसएफ में सीधी भर्ती के प्रत्येक भर्ती वर्ष में कुल रिक्तियों का आधा हिस्सा यानी 50 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेगा। इतना ही नहीं, पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता

परीक्षण से भी छूट दी जाएगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया उनके लिए और अधिक सरल हो जाएगी। सरकार का मानना है कि अग्निवीर पहले ही सैन्य प्रशिक्षण और शारीरिक दक्षता से गुजर चुके होते हैं, ऐसे में उन्हें दोबारा इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरने की आवश्यकता नहीं है।

इस अधिसूचना में अन्य आरक्षित वर्गों के लिए भी स्थिति स्पष्ट की गई है। इसके तहत बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में पूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत पद पहले की तरह आरक्षित रहेंगे, जबकि काम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के लिए अधिकतम 3 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं। सरकार का यह कदम सुरक्षा बलों में अनुभव और अनुशासन को प्राथमिकता देने की नीति को दर्शाता है।

भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी अधिसूचना में स्पष्ट व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार भर्ती दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत रिक्तियों पर भर्ती सीधे नोडल बल बीएसएफ द्वारा की जाएगी। इस चरण में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उन्हें जल्द से जल्द सेवा में शामिल होने का अवसर मिल सके। दूसरे चरण में शेष 47 प्रतिशत पदों पर भर्ती स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के माध्यम से की जाएगी, जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत आरक्षण लागू रहेगा।

अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि पहले चरण में किसी विशेष श्रेणी में पूर्व अग्निवीरों के पद खाली रह जाते हैं, तो उन रिक्तियों को दूसरे चरण में शामिल कर लिया जाएगा, ताकि कोई भी पद खाली न रहे। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निरंतरता बनी रहेगी।

केंद्र सरकार के इस फैसले को अग्निवीर योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले युवाओं के लिए भविष्य की सुरक्षा के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा सेवाओं में स्थायी अवसर दिए जाएं। बीएसएफ में 50 प्रतिशत आरक्षण का यह निर्णय न केवल उन मांगों का उत्तर है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि सरकार अग्निवीरों के कौशल, अनुशासन और देशभक्ति को राष्ट्र निर्माण में आगे भी उपयोग करना चाहती है।

इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि आने वाले समय में अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए इसी तरह की सुविधाएं और आरक्षण बढ़ाए जा सकते हैं। फिलहाल बीएसएफ में यह कदम लाखों युवाओं के लिए नई उम्मीद, स्थिर भविष्य और देश सेवा के निरंतर अवसर का रास्ता खोलता नजर आ रहा है।

गगनयान की सुरक्षित वापसी की दिशा में निर्णायक कदम, ड्रोग पैराशूट परीक्षणों में इसरो को बड़ी सफलता

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन की तैयारियों में एक और अहम उपलब्धि हासिल कर ली है। 18 और 19 दिसंबर को चंडीगढ़ में गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए विकसित किए गए ड्रोग पैराशूट के क्वालिफिकेशन टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए। इन परीक्षणों के साथ ही यह साबित हो गया है कि अंतरिक्ष से धरती पर लौटते समय क्रू मॉड्यूल को स्थिर रखने और उसकी तेज गति को नियंत्रित करने में ड्रोग पैराशूट पूरी तरह सक्षम और भरोसेमंद हैं।

इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार गगनयान मिशन में पैराशूट सिस्टम बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यही सिस्टम अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करेगा। जब क्रू मॉड्यूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो उसकी रफ्तार बेहद अधिक होती है। ऐसे में ड्रोग पैराशूट पहले चरण में खुलकर मॉड्यूल को स्थिर करते हैं और उसकी गति को काफी हद तक कम करते हैं, जिससे आगे के मुख्य पैराशूट सुरक्षित रूप से काम कर सकें। चंडीगढ़ में किए गए परीक्षणों के दौरान अलग-अलग ऊंचाइयों, गति और दबाव की परिस्थितियों में इन पैराशूटों की मजबूती, विश्वसनीयता और

कार्यक्षमता को परखा गया, जिसमें वे पूरी तरह सफल रहे।

इसरो ने बताया कि गगनयान के डीसेलरेशन सिस्टम में कुल 10 पैराशूट शामिल हैं, जो एक तय क्रम में खुलते हैं। यह पूरी प्रक्रिया बेहद सटीक और समयबद्ध होती है, क्योंकि किसी भी स्तर पर चूक होने से मिशन की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। ड्रोग पैराशूट के सफल परीक्षण के बाद अब इस जटिल प्रणाली के एक महत्वपूर्ण हिस्से को मंजूरी मिलने की राह साफ हो गई है, जो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

गगनयान मिशन के तहत भारत का लक्ष्य तीन अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है, जहां वे करीब तीन दिन तक रहेंगे। इसके बाद उन्हें सुरक्षित रूप से समुद्र में उतारा जाएगा। इस मिशन के जरिए भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल होगा, जिन्होंने अपने दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने और सुरक्षित वापस लाने की क्षमता हासिल की है।

ड्रोग पैराशूट के सफल क्वालिफिकेशन टेस्ट न केवल तकनीकी दृष्टि से अहम हैं, बल्कि यह भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में बढ़ते आत्मविश्वास को भी दर्शाते हैं। इस उपलब्धि से यह स्पष्ट होता है कि इसरो गगनयान मिशन को लेकर हर स्तर पर सुरक्षा, विश्वसनीयता और अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्राथमिकता दे रहा है। आने वाले समय में पैराशूट सिस्टम और अन्य महत्वपूर्ण घटकों के और परीक्षण किए जाएंगे, ताकि जब भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च हो, तो वह पूरी तरह सुरक्षित और सफल हो।

मोटापा बनता जा रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट, वजन घटाने की दवाओं के इस्तेमाल में सतर्कता जरूरी: डॉ. जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली। भारत में तेजी से बढ़ता मोटापा अब केवल व्यक्तिगत समस्या न रहकर एक गंभीर राष्ट्रीय स्वास्थ्य चुनौती का रूप ले चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि मोटापे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पूरे समाज को सामूहिक रूप से आगे आना होगा। उन्होंने वजन घटाने और मोटापा-रोधी दवाओं के इस्तेमाल को लेकर भी लोगों को सोच-समझकर निर्णय लेने की सलाह दी और चेतावनी दी कि बिना चिकित्सकीय परामर्श के इन दवाओं का प्रयोग नुकसानदायक हो सकता है। दो दिवसीय 'एशिया ओशिनिया मोटापा सम्मेलन' के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोटापा किसी व्यक्ति की सुंदरता या जीवनशैली

तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह एक जटिल, दीर्घकालिक और बार-बार उभरने वाला चिकित्सकीय विकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मोटापे को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह धीरे-धीरे शरीर को कई गंभीर बीमारियों की ओर धकेल देता है। इस समस्या के समाधान के लिए केवल दवाओं या तात्कालिक उपायों पर निर्भर रहने के बजाय बहु-आयामी और दीर्घकालिक रणनीति अपनाने की आवश्यकता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोटापे की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि अब इससे जुड़े गैर-संक्रामक रोग देश में मृत्यु के प्रमुख कारण बनते जा रहे हैं। टाइप-2 मधुमेह, हृदय रोग और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी बीमारियों के पीछे मोटापा एक बड़ा कारण है और ऐसे गैर-संक्रामक रोग कुल मृत्यु दर में लगभग 63 प्रतिशत का योगदान करते हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 के बाद से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में इन बीमारियों की रोकथाम, समय पर पहचान और शुरुआती हस्तक्षेप को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि मोटापे से लड़ाई केवल डॉक्टरों, पोषण विशेषज्ञों या महामारी वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। जिस तरह किसी देश की अर्थव्यवस्था को केवल अर्थशास्त्रियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, उसी तरह मोटापे जैसी व्यापक समस्या से निपटने के लिए नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, शिक्षण संस्थानों, मीडिया और आम नागरिकों सभी की साझा भूमिका जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों का एक मंच पर आना इस बात का संकेत है कि भारत में यह समस्या किस हद तक गंभीर होती जा रही है।

मनरेगा पर प्रहार, गरीबों के रोजगार अधिकार पर हमला: सोनिया गांधी

नई दिल्ली। मनरेगा की जगह लाए गए वीबी-जी राम जी विधेयक के संसद से पारित होने के बाद राजनीतिक घमासान और तेज हो गया है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने मनमाने तरीके से कानून पारित कर मनरेगा जैसी ऐतिहासिक और जनहितकारी योजना पर बुलडोजर चला दिया है। सोनिया गांधी ने वीबी-जी राम जी को "काला कानून" करार देते हुए इसके खिलाफ कांग्रेस की सड़कों से लेकर संसद तक लड़ाई जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है।

शीतकालीन सत्र समाप्त होने के एक दिन बाद जारी अपने वीडियो संदेश में सोनिया गांधी ने कहा कि मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं थी, बल्कि यह करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए सम्मान के साथ जीने का आधार बनी। उन्होंने 20 साल पहले का जिक्र करते हुए कहा कि जब डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री

थे, तब संसद में आम सहमति से मनरेगा कानून पारित किया गया था। यह कानून एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी। वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब तबके को पहली बार कानूनी रूप से रोजगार का अधिकार मिला। इससे गांवों से शहरों की ओर मजबूरी में होने वाले पलायन पर रोक लगी और लोगों को अपनी माटी, अपना गांव और अपने परिवार के साथ रहकर काम करने का अवसर मिला। ग्राम पंचायतों को सशक्त किया गया और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों को साकार करने की दिशा में एक मजबूत पहल हुई।

सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने लगातार मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण बेरोजगारों, किसानों, श्रमिकों और वंचित वर्गों के हितों की अनदेखी की गई, जबकि कोरोना महामारी के कठिन दौर में मनरेगा गरीबों के लिए संजीवनी साबित हुई थी। उस समय इसी योजना ने लाखों परिवारों को भुखमरी से बचाया और गांवों में रोजगार का सहारा दिया। उन्होंने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार ने न केवल मनरेगा को समाप्त कर दिया, बल्कि महात्मा गांधी का नाम भी इस योजना से हटा दिया। बिना व्यापक विचार-विमर्श, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए और बिना जमीनी सच्चाइयों को समझे मनरेगा का पूरा स्वरूप बदल दिया गया। अब यह तय किया जाएगा कि किसे, कितना, कहां और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह सब दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी, जो ग्रामीण भारत की वास्तविक जरूरतों से कोसों दूर है।

सोनिया गांधी ने स्पष्ट किया कि मनरेगा को लाने और लागू करने में कांग्रेस की भूमिका जरूर रही, लेकिन यह कभी किसी एक पार्टी की योजना नहीं थी। यह देशहित और जनहित से जुड़ी योजना थी, जिसने करोड़ों गरीबों को आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून को कमजोर कर मोदी सरकार ने देश के किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण गरीबों के हितों पर सीधा हमला किया है। अपने संदेश के अंत में सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ चुप बैठने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले गरीब भाई-बहनों को रोजगार का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया था और आज भी इस "काले कानून" के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

संपादकीय

चूक से हादसे

लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का वह बयान तार्किक ही है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं मानवीय व्यवहार से जुड़ी हैं। निश्चय ही यदि वाहन चालकों को सड़क व्यवहार के प्रति जागरूक किया जाए और हम जिम्मेदारी-सावधानी से वाहन चलाएं तो हर साल हजारों जिंदगियां बचायी जा सकती हैं। भारत में दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले कम वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं, लेकिन सड़क हादसों के मामले में हम अव्वल हैं। विडंबना देखिए कि एक साल में देश के भीतर करीब पांच लाख सड़क हादसे दर्ज किए जाते हैं। बड़ी संख्या उन हादसों की भी है जो छोटे शहरों व भीतरी इलाकों में होते तो हैं, लेकिन दर्ज नहीं होते। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश में हर साल करीब 1.8 लाख लोग इन हादसों में मारे जाते हैं। लाखों लोग इन हादसों में घायल होते हैं। हजारों लोग ऐसे भी होते हैं जो हादसों के बाद जीवनपर्यंत सामान्य जीवन नहीं जी पाते हैं। दुखद स्थिति यह भी है कि मरने वालों में सर्वाधिक संख्या युवाओं की होती है। एक आंकड़े के अनुसार मरने वालों में 66 फीसदी लोग 18 से 34 साल के बीच होते हैं। जो अपने परिवार के कमाने वाले व्यक्ति होते हैं। फलतः हादसे के बाद कई परिवार गरीबी के दलदल में धंस जाते हैं। दरअसल, सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण तेज गति से वाहन चलाना भी है। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि ओवर स्पीडिंग से 68 फीसदी से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। वहीं निर्धारित स्पीड से अधिक तेजी से वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं के चलते ही 68 फीसदी मौतें भी होती हैं। निश्चित रूप से ये हादसे व मौतें मानवीय व्यवहार की कमजोरी से जुड़े हैं। जहां देश में राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेस-वे का तेजी से विस्तार हुआ है तो बेहतर सड़कों में वाहन चालकों की गति अनियंत्रित हो चली है। जो कालांतर सड़क हादसों की वजह बनती है।

यह विडंबना है कि हम अकसर सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हैं। आज की युवा पीढ़ी हेलमेट पहनने से परहेज करती है। यह जानते हुए कि हादसों में सिर की चोट जानलेवा बन जाती है। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में हेलमेट न लगाने के कारण 54,568 लोगों की मौत हुई। वहीं सीट बेल्ट न लगाने से 16 हजार से अधिक यात्रियों की जान गई। इन हादसों की एक बड़ी वजह ऐसे अकुशल चालकों का होना भी था, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था। आंकड़ों के अनुसार दुर्घटनाओं के लिये जिम्मेदार चालकों में 33,827 ऐसे थे जिनके पास लाइसेंस नहीं थे। देश में बड़ी संख्या ऐसे चालकों की होती है, जो मेडिकली फिट नहीं होते। इसके अलावा जुगाड़ से ले-देकर लाइसेंस बनाने वालों की भी कमी नहीं है। वे वाहन चलाने की पर्याप्त योग्यता व अनुभव के बिना ही चालक बन बैठते हैं। हाल के वर्षों में नशे की हालात में वाहन चलाने का फैशन भी बना है। कई हादसों के बाद खुलासा हुआ कि फलां चालक नशे में धुत था। हालांकि, महानगरों व शहरों में नाका लगाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों की पकड़-धकड़ की जाती है। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेस-वे पर ऐसी जांच बड़े पैमाने पर होती नजर नहीं आती। वहीं ऐसे चालकों की भी कमी नहीं है, जो फोन पर बात करते हुए वाहन चलाते हैं। जिससे लगातार दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। निश्चित रूप से फोन पर बातचीत करता व्यक्ति भावावेश में उद्वेलित हो सकता है, जिससे वाहन चलाने की गुणवत्ता बाधित होती है। वाहन को सुरक्षित ढंग से चलाना भी एक कला है। चालक का मानसिक रूप से शांत होना भी जरूरी है। हाल के दिनों में सड़कों की बेहतर स्थितियों में लोगों में रात में सफर करने का रुझान बढ़ा है। गाहे-बगाहे चालक को झपकी लगने पर दुर्घटना होने के समाचार अकसर सुनने में आते हैं। निश्चित रूप से सड़क हादसों के मूल में तकनीकी कारण और सड़कों के डिजाइन व गुणवत्ता की भी भूमिका होती है। लेकिन हमारी नियंत्रित गति, सावधानी व सजगता दुर्घटनाएं टाल भी सकती है।

नाम बदलने की नीति व नीयत के सवाल

> किसी योजना में बदलाव का मतलब यही नहीं होना चाहिए कि उससे राजनीतिक स्वार्थ की गंध आये। देश-विदेश में गांधी की मूर्तियों के सम्मुख सर झुकाने से नहीं, गांधी के दिखाये मार्ग पर चलने से बदलाव आयेगा। गांधी का नाम हटाने की मानसिकता गांधी को नकारने का ही संकेत देती है।

बचपन में दोस्तों के बीच बहस के दौरान हम अक्सर एक वाक्य बोला करते थे—'अगर मेरी बात ग़लत सिद्ध हो तो मेरा नाम बदल देना'। हम नाम की दुहाई क्यों देते थे, पता नहीं, पर इतना अवश्य पता है कि हमारी मित्र-मंडली में नाम बदलने वाली इस बात का महत्व बहुत माना जाता था। नाम बदलने वाली यह बात आज अचानक 'मनरेगा' के नाम बदलने की सरकार की घोषणा के संदर्भ में याद आ रही है। याद यह भी आ रहा है कि अंग्रेजी के महान साहित्यकार शेक्सपियर ने कभी कहा था, नाम में क्या रखा है, गुलाब को कोई भी नाम दे दें, उसकी गंध तो नाम बदलने से नहीं बदलेगी'। शेक्सपियर की यह बात नाम के संदर्भ में अक्सर दुहराई जाती है। लेकिन यदि मामला 'मनरेगा' जैसी विकास योजना का हो तो बात सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं रह जाती, बात नाम बदलने की नीति से आगे बढ़कर नीयत तक पहुंच जाती है।

वर्ष 2005 में केन्द्र में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने 'मनरेगा' नाम से एक योजना प्रारंभ की थी। 'मनरेगा' का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह योजना नागरिकों को काम के अधिकार को दृष्टि में रख कर लागू की गयी थी, जिसमें किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को साल में कम से कम सौ दिन का रोज़गार उपलब्ध कराने की सरकार की गारंटी थी। जब यह योजना लागू हुई तो इस पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे थे। फिर जब केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनी तो प्रधानमंत्री ने इसे 'कांग्रेस की विफलताओं का जीता-जागता स्मारक' कहा था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि 'मैं इसे बंद नहीं करूंगा। मेरी राजनीतिक सोच

यह बताती है कि इसे कांग्रेस की विफलता के स्मारक के रूप में गाजे-बाजे के साथ बनाये रखना चाहिए'। सो, अपने ग्यारह साल के शासन में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे बनाये रखा। वस्तुतः यह एक ज़रूरत थी, और किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य में ऐसी ज़रूरत को दरकिनार नहीं किया जा सकता। मनरेगा की यह योजना कितनी उपयोगी सिद्ध हो रही है अथवा इसमें पहले कितना भ्रष्टाचार था और अब कितना भ्रष्टाचार है, यह मुद्दा अलग चर्चा का विषय हो सकता है। आज इस बारे में चर्चा करने की आवश्यकता सरकार की इस घोषणा से उत्पन्न हो गयी है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस योजना का नाम बदलना ज़रूरी हो गया है। सरकार ने निर्णय किया है कि अब इसे 'पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार' योजना कहा जायेगा– संक्षेप में 'जी रामजी विधेयक'। नाम बदलने के अलावा और भी कुछ बदलाव इस योजना में किए जा रहे हैं।

बदलाव पृथक बहस का विषय है, आज जो विवाद चल रहा है, वह यह है कि इस जन-उपयोगी योजना के नाम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम सरकार क्यों हटा रही है? इस संदर्भ में अब तक जो जवाब दिये जा रहे हैं, वे इस बात तक सीमित हैं कि आज़ादी के सौवें साल तक उन्नत भारत का सपना साकार करने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है! कहा यह भी जा रहा है कि नाम से क्या फर्क पड़ता है, महात्मा गांधी की जगह 'पूज्य बापू' का ही तो नाम दिया जा रहा है, फिर इसमें तो गांधी जी के आराध्य राम का नाम भी है। ऐसे में नाम बदलने से किसी को शिकायत क्यों होनी चाहिए? शिकायत इसलिए है कि बात सिर्फ महात्मा गांधी की जगह बापू नाम करने तक ही सीमित नहीं है—बात सरकार की नीयत की है। संसद में 'मनरेगा' की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 'राजनीतिक सूझ-बूझ' का भी हवाला दिया था। आज योजना का नाम बदलने के पीछे इस राजनीतिक सूझ-बूझ की बात नहीं कही जा रही है, पर आरोप भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर नाम बदलने वाली राजनीति का ही लग रहा है। पिछले दस-बारह साल में नाम बदलने वाली इस राजनीति की अक्सर चर्चा होती रही है। कांग्रेस लगातार यह आरोप लगाती रही है कि उसकी योजनाओं के नाम बदलकर वर्तमान सरकार यश लूटना चाहती है। इस नीति पर भी चर्चा हो सकती है, पर आज आवश्यकता इस बात की है कि योजनाओं, जगहों, नगरों आदि के नाम बदलकर की जाने वाली राजनीति का औचित्य क्या है? पिछले दस-बारह साल की ही बात करें तो पता चलता है कि न जाने कितनी जगहों, सड़कों आदि के नाम बदलकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश होती रही है। और यह लाभ उठाने का काम सिर्फ भाजपा ही नहीं कर रही। अलग-अलग समय पर अलग-अलग सरकारें ऐसा करती रही हैं और अब तो जैसे यह परंपरा बन गयी है। राजधानी दिल्ली में न जाने कितनी सड़कों के नाम बदल दिये गये हैं। पर समझने की बात यह है कि हर बदलाव प्रगति नहीं होता। राजपथ को कर्तव्य पथ कर देने मात्र से इस पथ पर चलने वालों की मानसिकता नहीं बदल जायेगी। मानसिकता का परिष्कार करने के लिए समाज की सोच को बदलने की आवश्यकता है। अतार्किक परिवर्तनों से बात नहीं बनती। ठोस परिवर्तनों की आवश्यकता है। सांस्कृतिक नवीनीकरण का तर्क अथवा इतिहास की कथित भूलों की दुहाई देकर बदले जाने वाले नाम भी कुल मिलाकर संकुचित सोच को ही दर्शाते हैं। आवश्यकता इस सोच से उबरने की है। यह भी समझना ज़रूरी है कि सिर्फ नाम बदलने से स्थितियां नहीं बदल जातीं। 'मनरेगा' योजना में यदि कोई बुराई थी तो इसलिए नहीं थी कि उसके साथ गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ था और सिर्फ इसलिए नये नाम वाली 'मनरेगा' अच्छी नहीं हो जायेगी कि उसके साथ अब भगवान राम का नाम जुड़ेगा। जिस रामराज्य की दुहाई बापू दिया करते थे, वह तुलसी का वह शासन था जिसमें 'नाही दरिद्र कोई दुखी न दीना' की स्थिति थी जहां जनता को 'दैहिक, दैविक भौतिक तापों' से मुक्ति मिली हुई थी। राम-राज्य में राजा राम जनता से कहते हैं कि यदि उनसे कोई चूक होती है तो वह अपने राजा को दंड दे सकती है। इस राम-राज्य को 'राजनीतिक सूझ-बूझ' से लिए गए निर्णयों से जोड़ना राम-राज्य की परिकल्पना से ही खिलवाड़ है। 'मनरेगा' का नाम-परिवर्तन शासन की राजनीतिक सूझ-बूझ पर आधारित होने का मतलब यही हो सकता है कि निर्णय के पीछे कहीं कोई राजनीतिक उद्देश्य है। नाम परिवर्तन की इस राजनीति से बचकर ही सही विकास की सीढ़ियां चढ़ी जा सकती हैं। शेक्सपियर ने भले ही कह दिया हो कि गुलाब का नाम बदलने से उसकी गंध नहीं बदल जाती पर राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए नाम बदलने की राजनीति से उबरना ज़रूरी है। विकास के संदर्भ में यह राजनीति कहीं नहीं पहुंचाएगी। फिर, इस सवाल का जवाब भी सरकार को देना ही होगा कि उसे 'मनरेगा' से महात्मा गांधी का नाम हटाना क्यों जरूरी लगा। वह महात्मा किसी एक राजनीतिक दल से नहीं समूचे राष्ट्र, और समूचे विश्व, से जुड़ा था। उसके नाम से चल रही किसी योजना में बदलाव का मतलब यही नहीं होना चाहिए कि उससे राजनीतिक स्वार्थ की गंध आये। देश-विदेश में गांधी की मूर्तियों के सम्मुख सर झुकाने से नहीं, गांधी के दिखाये मार्ग पर चलने से बदलाव आयेगा। गांधी का नाम हटाने की मानसिकता गांधी को नकारने का ही संकेत देती है।

प्रेरणा

एक बूंद से उठा तूफान, असावधानी की वह कथा जिसने पूरे राज्य को राख कर दिया

बहुत पुराने समय की बात है। अनंतदेव नाम के एक प्रतापी राजा थे, जिनका राज्य धन-धान्य से परिपूर्ण, प्रजा से भरा और शांति से संपन्न था। राजा को अपने वैभव, अनुशासन और व्यवस्था पर बड़ा गर्व था। राजमहल में हर काम नियम से होता था और नौकर-चाकर से लेकर मंत्री तक सभी अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहते थे। परंतु कहते हैं न, जब अहंकार और लापरवाही मन में घर कर लेती है, तब सबसे छोटी बात भी विनाश का कारण बन जाती है।

एक दिन राजा अनंतदेव अपने निजी कक्ष में भोजन कर रहे थे। सोने-चांदी के पात्रों में विविध व्यंजन परोसे गए थे। भोजन के दौरान उन्होंने शहद का पात्र उठाया। उसी समय उनके हाथ से थोड़ी-सी शहद की बूंद फिसलकर महंगे संगमरमर के फर्श पर गिर पड़ी। राजा की दृष्टि उस पर पड़ी, पर उन्होंने इसे तुच्छ समझा। उनके मन में विचार आया कि यह तो बहुत छोटी बात है, थोड़ी देर में कोई नौकर आएगा और स्वयं ही साफ कर देगा। यह सोचकर उन्होंने न तो नौकर को बुलाया और न ही स्वयं उसे साफ करने का प्रयास किया। यही वह क्षण था, जहां से विनाश की कहानी ने जन्म लिया।

कुछ समय बाद एक नौकर वहां आया। वह जल्दी में था, उसका ध्यान अपने काम पर था। उसकी नजर भी उस गिरी हुई शहद की बूंद पर नहीं पड़ी और वह बिना कुछ किए चला गया। शहद वहीं पड़ा रहा। थोड़ी देर में उसकी मिठास की खुशबू फैलने लगी और आसपास से मक्खियां उड़ती हुई वहां आ पहुंचीं। एक-दो नहीं, बल्कि दर्जनों मक्खियां शहद पर बैठकर उसे चाटने लगीं। उनकी भनभनाहट से वातावरण में हल्का-सा शोर होने लगा।

दीवार पर छिपी एक छिपकली की नजर उन मक्खियों पर पड़ी। उसे भोजन का सुनहरा अवसर दिखाई दिया और वह धीरे-धीरे रेंगती हुई नीचे उतर आई। जैसे ही वह मक्खियों को पकड़ने लगी, उसकी हलचल ने राजमहल में रहने वाली एक बिल्ली का ध्यान खींच लिया। बिल्ली वर्षों से राजमहल में पल रही थी और शिकार का अवसर मिलते ही वह झपट पड़ी। छिपकली को पकड़ने की कोशिश में बिल्ली ने इधर-उधर दौड़ लगाई, जिससे और शोर मच गया।

इसी शोरगुल के बीच संयोग से राजमहल के बाहर बगीचे में घूम रहे कुछ कुत्ते भीतर घुस आए। उन्होंने बिल्ली को देखा और अपने स्वभाव के अनुसार उस पर हमला कर दिया। बिल्ली किसी तरह फुर्ती से जान बचाकर भाग गई, लेकिन कुत्ते आपस में ही उलझ गए। देखते ही देखते कुत्तों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। दांत, पंजे और भौंकने की आवाज़ों से पूरा महल गूंज उठा। कई कुत्ते घायल हो गए और खून तक बहने लगा।

जब यह खबर कुत्तों के मालिकों तक पहुंची तो वे गुस्से में राजमहल आ धमके। हर व्यक्ति अपने कुत्ते को निर्दोष और दूसरे के कुत्ते को दोषी ठहराने लगा। पहले तो केवल बहस हुई, फिर बहस गाली-गलौज में बदली और अंततः मारपीट शुरू हो गई। धीरे-धीरे वहां आम लोग भी इकट्ठा होने लगे। भीड़ बढ़ती गई और भीड़ में छिपे असामाजिक तत्वों को उत्पात मचाने का अवसर मिल गया। उन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तोड़-फोड़ हुई, आगजनी की गई और अंत में राजमहल के एक बड़े हिस्से में आग लगा दी गई। जो राज्य कभी शांति और व्यवस्था के लिए जाना जाता था, वह कुछ ही घंटों में अराजकता और विनाश का प्रतीक बन गया।

काफी प्रयासों के बाद हालात पर काबू पाया गया। जब धुआं छंटा और आग बुझी, तब राजा अनंतदेव ने अपने मंत्रियों को बुलाया और इस भयानक उपद्रव का कारण जानना चाहा। मंत्री ने गहन जांच की, हर कड़ी को जोड़ा और अंत में सत्य राजा के सामने रखा। उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, इस पूरे विनाश की जड़ वह शहद की बूंद है जो भोजन करते समय आपसे फर्श पर गिर गई थी। यदि उस छोटी-सी बात को उसी समय संभाल लिया गया होता, तो न मक्खियां आतीं, न छिपकली, न बिल्ली, न कुत्तों की लड़ाई और न ही यह भयानक दंगा होता।

यह सुनकर राजा अनंतदेव के हृदय में पश्चाताप की ज्वाला उठी। उन्हें पहली बार समझ आया कि राजा होने के बावजूद वे भी एक छोटी-सी असावधानी के दोषी हैं। उसी दिन उन्होंने निश्चय किया कि राज्य में छोटी से छोटी समस्या को भी गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने प्रजा को यह शिक्षा दी कि किसी भी गलती या चूक को समय रहते सुधार लेना चाहिए, क्योंकि जो आज मामूली लगती है, वही कल विनाश का कारण बन सकती है।

यह कथा केवल एक राजा और उसके राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि हर मनुष्य के जीवन का आईना है। यह हमें सिखाती है कि लापरवाही, अहंकार और टालने की प्रवृत्ति धीरे-धीरे बड़े संकटों को जन्म देती है। जीवन में यदि हम छोटी समस्याओं को समय पर सुलझा लें, तो बड़े तूफानों से स्वयं को और अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं।

सेकुलरवाद का बहाना वोटरों पर निशाना

बिहार में जाति-धर्म की सियासी पिच पर बुरी तरह मात खाने के बावजूद इंडिया गठबंधन का भरोसा इसी पर है। तमिलनाडु में जिस तरह कार्तिगई दीपम परंपरा स्थापित करने का आदेश देने वाले मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश जी आर स्वामीनाथन के खिलाफ गठबंधन ने लामबंदी की है, उससे यही संकेत मिल रहे हैं। डीएमके सांसद कनिमोई की अगुआई में विपक्षी गठबंधन के 120 सांसदों द्वारा स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का नोटिस देना गठबंधन की पारंपरिक राजनीति का ही विस्तार है। विपक्षी गठबंधन यह पचा नहीं पा रहा है कि कथित सेकुलर देश में किसी जज ने बहुसंख्यक सनातनी परंपरा स्थापित करने का निर्णय दे दिया है। स्वामीनाथन के फैसले के अनुसार, जहां कार्तिदीपम मनाया जाना है, वहां एक दरगाह भी है। दरगाह और मंदिर साथ हो तो मंदिर की कीमत पर दरगाह की परंपराएं अपने यहां चलती रही हैं। अब तक की शासन व्यवस्था के लिहाज से ऐसे मामलों में मंदिर के पक्ष में फैसला सवालों के घेरे में आता है। स्वामीनाथन ने मदुरै जिले की थिरूपरनकुंद्रम की पहाड़ी की चोटी पर कार्तिगई दीपम की परंपरा को स्थापित करने की मंजूरी दी है, जिसे 1920 के एक विवाद के बंद कर दिया गया था। यह बात और है कि डीएमके की अगुआई वाली तमिलनाडु सरकार ने विवाद की आशंका के बहाने अदालत के फैसले को लागू ही नहीं होने दिया। दिलचस्प है कि अल्पसंख्यक समुदाय ने इसका विरोध भी नहीं किया, बल्कि सरकार ही खुद आगे बढ़कर विवाद की आशंका से भर उठी। राज्य सरकार ने स्वामीनाथन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है। लेकिन इस फैसले के लिए स्वामीनाथन को पचा नहीं पा रही है। उसे लगता है कि अगर उसने जज को सबक नहीं सिखाया तो उसकी सेकुलरवाद के बुनियाद पर टिकी राजनीति में दरार पड़ सकती है। जज को सबक सिखाने और न्यायपालिका पर अंकुश लगाने के डीएमके के इस कदम में सबसे हैरतनाक कदम है, अखिलेश यादव का बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना। लोकसभा अध्यक्ष को महाभियोग प्रस्ताव पेश करते वक्त कनिमोई के साथ कांग्रेसी नेताओं और अखिलेश की मौजूदगी के संकेत गहरे हैं। दरअसल महागठबंधन के दल अल्पसंख्यक समुदाय को यह संकेत देने की कोशिश में हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन ही उसके हितों के लिए किसी जज को भी सूली पर चढ़ा सकता है। महागठबंधन की कोशिश कुछ महीने बाद होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए राज्य की करीब छह फीसद अल्पसंख्यक आबादी को लुभाना भी है। वैसे देखा जाए तो राज्य की सात करोड़ 21 लाख की आबादी में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या महज 42 लाख तीस हजार ही है। ब्राह्मणवाद की बुनियाद पर उभरी डीएमके की राजनीति में अल्पसंख्यकवाद पिछड़ी जातियों को लुभाने का भी मंत्र रहा है। राज्य की अधिसंख्य पिछड़ी आबादी को भी लुभाने की इस बहाने की कोशिश हो रही है। इसीलिए कार्तिगई दीपम की परंपरा को रोकने में डीएमके को कोई हिचक नहीं हुई।

इस पूरे मसले पर चर्चा से पहले जानना जरूरी है कि कार्तिगई दीपम त्योहार है क्या? दक्षिम के दीप पर्व के रूप में विख्यात कार्तिगई दीपम भगवान मुरूगन के सम्मान में तमिल महीने में दीप जलाने की परंपरा है। शिव और पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय तमिलनाडु में मुरूगन और सुब्रह्मण्यम के नाम से भी जाने जाते हैं। मदुरै जिले की जिस थिरुपरनकुंद्रम की पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम मनाने का आदेश अदालत ने दिया, वह भगवान मुरूगन की छह पवित्र जगहों में से एक है। मान्यता है कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद को सुलझाने के लिए शिवजी स्वयं अनंत अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। उसी दीप स्तंभ की स्मृति स्वरूप उचिपिल्लियर मंदिर के पास प्राचीन दीपाथुन नामक स्तंभ के नजदीक महादीपक जलाया जाता है। थिरूपरनकुंद्रम की पहाड़ी पर भी इसकी परंपरा रही। लेकिन बाद में वहां मंदिर के नजदीक ही एक दरगाह स्थापित हो गई। दरगाह के बाद सेकुलरवाद को बढ़ावा देना जरूरी था, लिहाजा दीपम की परंपरा अधिकारियों ने रोक दी। जिसे शुरू करने को लेकर अदालती हस्तक्षेप की मांग की गई। पहले मदुरै की जिला अदालत में मामला चला और बाद में मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने पहाड़ी पर दीप जलाने की परंपरा शुरू करने का आदेश दिया। इसके बाद पहाड़ी पर तीन दिसंबर को दीप जलाने श्रद्धालुओं का जमावड़ा होने लगा। लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। राज्य की स्टालिन सरकार का कहना था कि इससे खून-खराबा हो सकता है। जबकि अल्पसंख्यकों की ओर से ऐसी कोई कोशिश या बयानबाजी भी नहीं हुई थी। बहरहाल, डीएमके सरकार के इस फैसले ने राज्य में पैर जमाने की कोशिश में बैठी बीजेपी को मुद्दा दे दिया। पार्टी का कहना है कि डीएमके सेक्युलरिज्म की बात करती तो है, लेकिन उसके निशाने पर सिर्फ़ हिंदू समुदाय ही रहता है। बीजेपी का आरोप है कि डीएमके ने कभी किसी गैर हिंदू परंपरा, दरगाह या आदि पर कभी कोई सवाल नहीं खड़ा किया। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर राज्य के हिंदुओं ने कौन सी गलती की है कि उन्हें दीप जलाने के अधिकार के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है।

डीएमके की पूर्ववर्ती जस्टिस पार्टी की स्थापना 1916 में हुई थी। उसका घोषित उद्देश्य एनी बेसेंट की अगुआई वाले होम रूल लीग आंदोलन का विरोध था। जस्टिस पार्टी का मानना था कि अगर होमरूल आंदोलन सफल हुआ तो तमिलनाडु में जारी ब्राह्मणवाद की वजह से ब्राह्मण अधिकारियों की तादाद बढ़ जाएगी। एक तरह से कह सकते हैं कि जस्टिस पार्टी की स्थापना ब्राह्मणवाद के विरोध के लिए हुई थी। कालांतर में उसकी ब्राह्मणवाद विरोध की राजनीति बढ़ते-बढ़ते ब्राह्मण विरोध पर केंद्रित हो गई। बाद में उसके विरोध के दायरे में हिंदी और पूरी सनातन परंपरा समा गई। यही वजह है कि स्टालिन कुनबे को हिंदुत्व की कटु आलोचना से कभी परहेज नहीं रहता। अहर्निश हिंदी विरोध और अब कार्तिगई दीपम का विरोध इसी परंपरा का विस्तार है।

अभियान

पर्वतों की शांति में गूंजती श्रद्धा, चमत्कारों से रचा विश्वास और भारतीय संस्कृति की दिव्य गाथा

तेलंगाना की धरती पर स्थित स्वर्णगिरी वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह उस गहरी आस्था और विश्वास की जीवंत कहानी है, जहां मानव की उम्मीदें ईश्वर की कृपा से नया जीवन पाती हैं। भुवनगिरी क्षेत्र की मानेपल्ली पहाड़ियों पर विराजमान यह मंदिर जैसे ही दृष्टि में आता है, मन अपने आप श्रद्धा से भर उठता है। हैदराबाद से लगभग सैंतालीस किलोमीटर दूर फैला यह विशाल परिसर बाइस एकड़ में विस्तृत है और जिस पहाड़ी पर यह बना है, उसे स्वर्णगिरि नाम देकर इसे पवित्रता का प्रतीक बनाया गया है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह धाम दूर से ही भक्तों को अपनी ओर बुलाता प्रतीत होता है।

इस मंदिर की वास्तुकला भारतीय शिल्प परंपरा का भव्य उदाहरण है। इसके निर्माण में विजयनगर, पल्लव, चोल और चालुक्य काल की स्थापत्य शैलियों का अद्भुत समन्वय किया गया है। चारों दिशाओं में बने विशाल राजगोपुरम मंदिर को राजसी गरिमा प्रदान करते हैं। जैसे ही श्रद्धालु इन गोपुरमों से भीतर प्रवेश करता है,

उसे विशाल मंडपों, नक्काशीदार स्तंभों और खुले प्रांगणों का दिव्य दृश्य दिखाई देता है। गर्भगृह के ऊपर बना पांच मंजिला विमान गोपुरम इस मंदिर की पहचान बन चुका है, जो आकाश की ओर उठती भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है।

मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान श्री वेंकटेश्वर की बारह फुट ऊंची प्रतिमा इस धाम की आत्मा है। यह प्रतिमा न केवल तेलंगाना की सबसे ऊंची वेंकटेश्वर प्रतिमा मानी जाती है, बल्कि इसकी भव्यता और दिव्यता भक्तों के हृदय को गहराई से छू जाती है। भगवान का शांत मुखमंडल, करुणामय दृष्टि और अलौकिक तेज ऐसा प्रतीत कराता है मानो स्वयं भगवान अपने भक्तों को आश्वस्त कर रहे हों कि वे सदैव उनके साथ हैं।

इस भव्य मंदिर के निर्माण के पीछे जुड़ी कथा इसे और भी पवित्र बना देती है। प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमन मानेपल्ली रामाराव के जीवन में आया वह कठिन दौर, जब उनकी पत्नी श्रीमति विजयलक्ष्मी एक गंभीर सड़क दुर्घटना के बाद कोमा में चली गई थीं, पूरे परिवार के लिए असहनीय पीड़ा लेकर आया। जब चिकित्सकों ने सभी प्रयासों के बाद हाथ खड़े कर दिए, तब परिवार ने भगवान वेंकटेश्वर की शरण ली। तिरुपति का पवित्र जल उन्हें पिलाया गया और उसके बाद धीरे-धीरे उनकी स्थिति में सुधार होने लगा। यह घटना परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। इसी दिव्य कृपा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए परिवार ने भगवान के नाम पर एक भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प लिया, जो वर्षों की साधना और प्रयास के बाद स्वर्णगिरी वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के रूप में साकार हुआ।

मंदिर परिसर की भव्यता यहीं समाप्त नहीं होती। यहां स्थापित एक सौ बीस फुट ऊंचा हनुमान मंडप शक्ति और भक्ति का प्रतीक बनकर आकाश को स्पर्श करता हुआ प्रतीत होता है। एक ही पत्थर से निर्मित चालीस फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा भारतीय शिल्पकला की अद्वितीय मिसाल है। इसके अतिरिक्त मंदिर में स्थापित भारत की दूसरी सबसे बड़ी कांसे की घंटी, जिसका वजन लगभग डेढ़ टन है, जब गूंजती है तो उसका नाद पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देता है। संध्या के समय जला नारायण स्वामी सन्निधि जब रोशनी से जगमगाती है, तो पूरा परिसर किसी दिव्य लोक का आभास कराता है।

स्वर्णगिरि वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यहां सुबह की आरती से लेकर रात की शेज आरती तक निरंतर भक्ति का प्रवाह बना रहता है। वर्ष भर श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन मानसून और शीत ऋतु में यहां की प्राकृतिक सुंदरता अपनी चरम सीमा पर होती है। बारिश के बाद हरियाली से ढकी पहाड़ियां, बादलों से घिरा आकाश और ठंडी हवाएं मिलकर पूरे वातावरण को स्वर्ग जैसा बना देती हैं। ऐसे समय में मंदिर दर्शन केवल धार्मिक अनुभव नहीं, बल्कि प्रकृति और आत्मा के मिलन जैसा अनुभव बन जाता है।

यात्रा की सुविधा के लिहाज से भी यह मंदिर अत्यंत सुगम है। हैदराबाद का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यहां से लगभग छिहत्तर किलोमीटर दूर है, जहां से टैक्सी द्वारा आसानी से मंदिर पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग से आने वाले श्रद्धालु भोंगिर जंक्शन या सिकंदराबाद जंक्शन तक पहुंचकर सड़क मार्ग से मंदिर जा सकते हैं। सड़क मार्ग से हैदराबाद से भुवनगिरी तक सीधी बस और निजी वाहन सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे यात्रा सरल और सहज हो जाती है।

स्वर्णगिरि वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर वास्तव में उस विश्वास की अमर गाथा है, जहां मानव की आस्था ईश्वर की कृपा से आकार लेती है। यह धाम न केवल भगवान वेंकटेश्वर की महिमा का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, भक्ति और चमत्कार की एक जीवंत मिसाल भी है। यहां आकर हर श्रद्धालु अपने जीवन की थकान, चिंता और दुख को पीछे छोड़कर भगवान के चरणों में शांति, सुकून और दिव्यता का अनुभव करता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा

लोक सेवक रहते हुए अवैध संपत्ति जुटाने और धनशोधन के आरोपों में ईडी की कड़ी कार्रवाई, पीएमएलए कोर्ट में दाखिल हुई चार्जशीट

दमन। दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेश) में सार्वजनिक जीवन की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करने वाले एक अहम मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद ने तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष केतन पटेल के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने और धनशोधन के आरोपों में दमन स्थित पीएमएलए विशेष अदालत में अभियोग दायर किया है। यह कार्रवाई वर्षों तक चली जांच, दस्तावेजी सबूतों और वित्तीय लेन-देन के विश्लेषण के बाद सामने आई है, जिसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसियों की सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है।

इस मामले की शुरुआत केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज एफआईआर से हुई थी। सीबीआई ने 04 अक्टूबर 2005 से 05 अक्टूबर 2015 के बीच लोक सेवक रहते हुए केतन पटेल द्वारा अपनी वैध आय से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की जांच की थी। जांच में भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। सीबीआई की पड़ताल में यह सामने आया कि उनकी घोषित आय और वास्तविक संपत्तियों के बीच बड़ा अंतर है। इसके बाद सीबीआई ने करीब 3.77 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति को लेकर चार्जशीट दाखिल की, जिसके आधार पर ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत अलग से जांच शुरू की।

ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ कि केतन पटेल ने अपने कार्यकाल के दौरान कथित रूप से भ्रष्टाचार से अर्जित धन को विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से जमा कराया। खातों में बड़ी मात्रा में नकद जमा और संदिग्ध

लेन-देन पाए गए, जिनका कोई स्पष्ट और वैध स्रोत नहीं बताया जा सका। जांच एजेंसी के अनुसार, इन पैसों का इस्तेमाल होटल में ठहरने, महंगी खरीदारी और अन्य निजी खर्चों के लिए किया गया। पूछताछ के दौरान इन प्रविष्टियों को 'ऋण' बताने का प्रयास किया गया, लेकिन न तो ऐसे किसी ऋण का ठोस रिकॉर्ड मिला और न ही उसकी वापसी का कोई प्रमाण सामने आया, जिससे ईडी का संदेह और गहराता गया।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि अवैध रूप से अर्जित धन को वैध दिखाने के लिए फर्जी वित्तीय प्रविष्टियों का सहारा लिया गया। ईडी का मानना है कि यह पूरा तंत्र धनशोधन की मंशा से तैयार किया गया था, ताकि अवैध कमाई को छिपाया जा सके और उसे संपत्तियों व निवेश के रूप में बदला जा सके। इसी आधार पर ईडी ने पहले ही मुंबई स्थित वाणिज्यिक इकाइयों और दुकानों, एक भूखंड तथा फिक्स्ड डिपॉजिट सहित कुल 3.77 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया था।

अब पीएमएलए विशेष अदालत में अभियोग दाखिल होने के बाद यह मामला कानूनी रूप से एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। आने वाले समय में अदालत में प्रस्तुत किए जाने वाले सबूतों और गवाहियों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। यह मामला न केवल एक पूर्व जनप्रतिनिधि की भूमिका पर सवाल उठाता है, बल्कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर भी एक कड़ा संदेश देता है कि भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति के मामलों में कानून अपना काम करेगा।

अहमदाबाद को मिली उसकी पहली 'मेक इन इंडिया' मेट्रो ट्रेन

- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कोलकाता स्थित टीटागढ़ रेल सिस्टम्स प्लांट में गुजरात की सांस्कृतिक भावना को प्रतिबिंबित करने वाली अत्याधुनिक एवं आत्मनिर्भर भारत की प्रतीक समान ट्रेन का स्वागत किया
- यह मेट्रो ट्रेन श्रेष्ठ कोटि की फायर सेफ्टी सहित अन्य सुरक्षा सुविधाओं तथा ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन 4 (जीओए4) के अंतर्गत पूर्णतः ऑटोमेटेड-ड्राइवरलेस ट्रेन के रूप में कार्य करने में सक्षम है

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को अहमदाबाद शहर को उसकी प्रथम स्वदेशी रूप से निर्मित 'मेक इन इंडिया' मेट्रो ट्रेन की भेंट दी।

श्री पटेल ने कोलकाता के निकट टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के आधुनिक प्लांट का दौरा कर अहमदाबाद मेट्रो रेल के कोचेस लॉन्च किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'मेक इन इंडिया' तथा आत्मनिर्भर भारत को गति देने वाला यह महत्वपूर्ण कदम गुजरात के लिए गौरव समान है।

टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा उसके फैसिलिटी प्लांट में यह ट्रेन मेक इन इंडिया अंतर्गत स्वदेशी रूप से बनाई जा रही है। आधुनिक मेट्रो तथा यात्री कोच के उत्पादन के लिए सक्षम यह प्लांट अत्याधुनिक एवं आधुनिक तकनीक तथा साधन-सामग्री के साथ स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीटागढ़ प्लांट में देश के अनेक राज्यों के लोग कार्यरत हैं। यह भी एक भारत-श्रेष्ठ भारत का प्रधानमंत्री का मंत्र चरितार्थ करता है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए अभिनंदन दिया।

उन्होंने कहा कि अहमदाबाद को मिल रही यह मेट्रो ट्रेन शहर में मेट्रो रेल व्यवस्था की बढ़ती मांग तथा लोकप्रियता को पूरा करने के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को सुगम बनाएगी। गुजरात मेट्रो रेल

कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएमआरसीएल) ने कोलकाता स्थित टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड को 10 ट्रेनों का ऑर्डर दिया है। ये ट्रेनें फेज-2 के 21 किलोमीटर का कार्य पूर्ण होने पर तथा शेष भाग शीघ्र कार्यरत होने पर उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त ट्रेनों की जरूरत को पूरा करेंगी।

श्री भूपेंद्र पटेल ने जोड़ा कि अहमदाबाद मेट्रो हाल में प्रतिदिन 1.6 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा देती है और इसमें वार्षिक 30-40 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। आने वाले दिनों में मेट्रो रेल सेवा का यह दायरा बढ़ाया जाएगा और सूरत में भी मेट्रो कार्यरत होने वाली है।

उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील से बनी इन मेक इन इंडिया ट्रेनों में रंगों तथा डिजाइन का जो विशेष स्पर्श दिया गया है, वह अहमदाबाद की संस्कृति एवं परंपरा को प्रतिबिंबित करता है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि अहमदाबाद मेट्रो रेल के लिए स्वीकार की गई प्रथम मेक इन इंडिया मेट्रो ट्रेन अंतिम परीक्षणों तथा सम्बद्ध प्राधिकारियों से प्रमाणपत्र मिलने के बाद शीघ्र ही अहमदाबाद पहुँचाई जाएगी। इसके बाद उसे यात्रियों की सेवा में जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं; अहमदाबाद के लिए बाकी रही 9 ट्रेनें भी टीटागढ़ प्लांट द्वारा आगामी 5-6 महीनों में चरणबद्ध ढंग से प्रदान की जाएंगी। वैश्विक स्तर पर लागू होने वाले वर्तमान अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुकूल यह मेक इन इंडिया ट्रेन गुजरात के लिए गौरव समान बनेगी।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ऐसे विजनरी लीडर हैं कि वे हर कार्य में भावी आयोजन तथा छोटे से छोटे व्यक्ति के भले का विचार करके ही आगे बढ़ते हैं। उनके दिशादर्शन में देश के विकास में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उसका विवरण देते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि पिछले वर्षों में देश में रिकॉर्ड ब्रेक गति से सड़क निर्माण हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है और मेक इन इंडिया सेमी हाईस्पीड वंदे भारत ट्रेन से रैपिड ट्रांजिस्ट को नई दिशा मिली है। 2014 में मेट्रो नेटवर्क 248 किलोमीटर था, जो 2025 में बढ़कर 1013 किलोमीटर हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कोच निरीक्षण के जरिये तथा प्लांट के वरिष्ठ इंजीनियरों के साथ चर्चा करते हुए अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन के कोचेस की विशेषताओं की गहन जानकारी प्राप्त की। टीटागढ़ प्लांट के इंजीनियरों ने मुख्यमंत्री को बताया कि यह मेट्रो ट्रेन श्रेष्ठ कोटि की फायर सेफ्टी सहित अन्य सुरक्षा सुविधाओं तथा ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन 4 (जीओए4) अंतर्गत पूर्णतः ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन के रूप में कार्य करने में सक्षम है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, मुख्यमंत्री के सलाहकार तथा गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री एस. एस. राठौड़, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के प्रबंध निदेशक श्री उमेश चौधरी, गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन तथा टीटागढ़ रेलवे सिस्टम्स के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

टीटागढ़ रेलवे सिस्टम्स प्लांट नेक्स्ट जनरेशन वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों तथा पुणे, बेंगलुरू, मुंबई, सूरत एवं अहमदाबाद जैसे अनेक शहरों के लिए मेट्रो ट्रेनों के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। इस प्लांट में भारत के महत्वाकांक्षी हाईस्पीड कार्यक्रम के लिए भविष्य में उच्च गति की ट्रेनें बनाने की क्षमता विकसित करने के लिए भी सुविधाओं का विकास कार्य शुरू किया गया है। इतना ही नहीं; कंपनी भारत की सबसे बड़ी वेगन उत्पादक कंपनी है और नौसेना तथा अन्य विशेष उपयोगों के लिए जहाजों का उत्पादन भी करती है।

आदरज मोटी–विजापुर रेलखंड पर इंजन स्पीड ट्रायल सफलता पूर्वक सम्पन्न

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर आदरज मोटी–विजापुर गेज परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत आदरज मोटी–विजापुर सेक्शन में नई परिवर्तित ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पर 20 दिसंबर 2025 को लाइट इंजन का स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया। यह स्पीड ट्रायल किमी 6/4 से किमी 45/1 के बीच अधिकतम 136 किमी प्रति घंटे की गति से संपन्न हुआ। इस रेलवे लाइन के पूर्ण होने पर हाल ही में गेज परिवर्तित आंबलियासन-विजापुर लाइन से सीधी जुड़ जाएगी।

इस स्पीड ट्रायल के सफल आयोजन से आगामी समय में इस खंड पर तेज, सुरक्षित एवं सुगम रेल परिचालन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आंबलियासन को इस नई ब्रॉडगेज रेल लाइन से विशेष रूप से उत्तर गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी प्राप्त होगी, जिससे यात्रियों को समय की बचत के साथ अधिक सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी।

स्पीड ट्रायल रेलवे की एक अनिवार्य तकनीकी प्रक्रिया है, जो रेल परिचालन प्रारंभ करने से पूर्व ट्रैक की गुणवत्ता, स्थिरता एवं सुरक्षा मानकों की जांच हेतु की जाती है। इस दौरान विभागीय ट्रेनें, मापन यंत्र एवं तकनीकी विशेषज्ञों की टीम द्वारा ट्रैक का गहन परीक्षण किया गया।

यात्री सुविधा एवं अवसंरचना विकास हेतु ट्रैफिक ब्लॉक के कारण भावनगर मंडल की कुछ ट्रेनों के संचालन में अस्थायी परिवर्तन

यात्रियों को सूचित किया जाता है कि पश्चिम रेलवे के मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में छठी लाइन के कमीशनिंग कार्य के लिए ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लिया जा रहा है। यह कार्य रेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा भविष्य में अधिक सुचारु रेल परिचालन सुनिश्चित करने की दिशा में किया जा रहा है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि उक्त कार्य के दौरान भावनगर रेलवे मंडल से संबंधित कुछ मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन में अस्थायी परिवर्तन किए गए हैं। प्रभावित ट्रेनों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:-

1.ट्रेन नंबर 19218 वेरावल-बान्द्रा एक्सप्रेस 27.12.2025 को 01 घंटा रिशेड्यूल होगी अर्थात वेरावल से 01 घंटा विलंब से चलेगी।

2.ट्रेन नंबर 19218 वेरावल-बान्द्रा एक्सप्रेस 10.01.2026 को 45 मिनट

रिशेड्यूल होगी अर्थात् वेरावल से 45 मिनट विलंब से चलेगी।

3.ट्रेन नंबर 19218 वेरावल-बान्द्रा एक्सप्रेस 15.01.2026 को 45 मिनट रिशेड्यूल होगी अर्थात् वेरावल से 45 मिनट विलंब से चलेगी।

4.ट्रेन नंबर 19218 वेरावल-बान्द्रा एक्सप्रेस 16.01.2026 को 30 मिनट रिशेड्यूल होगी अर्थात् वेरावल से 30 मिनट विलंब से चलेगी।

5.ट्रेन नंबर 12972 भावनगर-बान्द्रा सुपरफास्ट 27.12.2025 को मार्ग में 45 मिनट रिशेड्यूल होगी अर्थात् मार्ग में 45 मिनट विलंब होगी।

6.ट्रेन नंबर 19218 वेरावल-बान्द्रा एक्सप्रेस 06.01.2026 को मार्ग में 15 से 20 मिनट रिशेड्यूल होगी अर्थात् मार्ग में 15 से 20 मिनट विलंब होगी।

7.ट्रेन नंबर 19218 वेरावल-बान्द्रा एक्सप्रेस 07.01.2026 को मार्ग में 15 से 20 मिनट रिशेड्यूल होगी अर्थात् मार्ग में 15 से 20 मिनट विलंब होगी।

8.ट्रेन नंबर 19218 वेरावल-बान्द्रा एक्सप्रेस 13.01.2026 को मार्ग में 15 से 20 मिनट रिशेड्यूल होगी अर्थात् मार्ग में 15 से 20 मिनट विलंब होगी।

9.ट्रेन नंबर 19218 वेरावल-बान्द्रा एक्सप्रेस 14.01.2026 को मार्ग में 15 से 20 मिनट रिशेड्यूल होगी अर्थात् मार्ग में 15 से 20 मिनट विलंब होगी।

10.ट्रेन नंबर 09208 वेरावल-बान्द्रा टीओडी स्पेशल 15.01.2026 को मार्ग में 20 मिनट रिशेड्यूल होगी अर्थात् मार्ग में 20 मिनट विलंब होगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा से पूर्व NTES ऐप, रेलवे पूछताछ (139) अथवा अधिकृत रेलवे वेबसाइट के माध्यम से अपनी ट्रेन की स्थिति की पुष्टि कर लें। आरक्षित यात्रियों को SMS अलर्ट के माध्यम से भी जानकारी प्रदान की जा रही है।

पश्चिम रेलवे यात्रियों से इस असुविधा के लिए खेद प्रकट करता है तथा सहयोग की अपेक्षा करता है। यह कार्य पूर्ण होने के पश्चात यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित एवं समयबद्ध रेल सेवाओं का लाभ मिलेगा।

पश्चिम रेलवे का 45वाँ अधिकारियों का वार्षिक खेलकूद समारोह-क्रिकेट टूर्नामेंट में अहमदाबाद मंडल की शानदार जीत

पश्चिम रेलवे द्वारा आयोजित 45वें अधिकारियों के वार्षिक खेलकूद समारोह के अंतर्गत क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में पश्चिम रेलवे के विभिन्न मंडलों एवं मुख्यालय की टीमें भाग ले रही हैं। पश्चिम रेलवे 45वी अधिकारियों की खेलकूद प्रतियोगिता क्रिकेट टूर्नामेंट 2025–26 टूर्नामेंट का दूसरा मैच आज दिनांक 20 दिसंबर 2025 को अहमदाबाद मंडल स्पोर्ट्स ग्राउंड (ADSA), साबरमती में खेला गया। इस क्रिकेट मैच के दौरान अहमदाबाद मण्डल के मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश और मण्डल रेल प्रबंधक-भावनगर श्री दिनेश वर्मा भी मौजूद रहे। इस मैच में अहमदाबाद मंडल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में भावनगर मंडल की टीम 20 ओवरों में 7 विकेट पर 118 रन ही बना सकी। इस प्रकार अहमदाबाद मंडल ने यह मैच 64 रनों से जीत लिया। श्री प्रशांत सिंह Dy CE III अहमदाबाद के इस मैच के प्रमुख खिलाड़ी रहे, इन्होने शतक लगा कर अपनी टीम को विजय दिलाई तथा मैच ऑफ द मैच एवं बेस्टमेन रहे। बेस्ट बॉलर श्री विकास कुमार,Sr DSTE अहमदाबाद रहे। यह मैच खेल भावना, टीमवर्क एवं आपसी सहयोग का अच्छा उदाहरण रहा।

लीग चरण का कार्यक्रम

ग्रुप 'A'

- राजकोट बनाम अहमदाबाद – 13 दिसंबर 2025, प्रातः 09:30 बजे (राजकोट)
- अहमदाबाद बनाम भावनगर – 20 दिसंबर 2025, प्रातः 09:30 बजे (अहमदाबाद)
- वडोदरा बनाम राजकोट – 20 दिसंबर 2025, प्रातः 09:30 बजे (वडोदरा)
- भावनगर बनाम वडोदरा – 27 दिसंबर 2025, प्रातः 09:30 बजे (राजकोट)
- अहमदाबाद बनाम वडोदरा – 03 जनवरी 2026, प्रातः 09:30 बजे (अहमदाबाद)
- राजकोट बनाम भावनगर – 04 जनवरी 2026, प्रातः 09:30 बजे (भावनगर)

ग्रुप 'B'

- रतलाम बनाम मुंबई सेंट्रल (BCT) – 21 दिसंबर 2025, प्रातः 09:30 बजे (रतलाम)
- मुख्यालय 'A' बनाम मुख्यालय 'B' – 21 दिसंबर 2025, प्रातः 09:30 बजे (महालक्ष्मी)
- रतलाम बनाम मुख्यालय 'A' – 28 दिसंबर 2025, प्रातः 09:30 बजे (महालक्ष्मी)
- मुख्यालय 'B' बनाम मुंबई सेंट्रल (BCT) – 02 जनवरी 2026, प्रातः 09:30 बजे (महालक्ष्मी)
- मुख्यालय 'A' बनाम मुंबई सेंट्रल (BCT) – 03 जनवरी 2026, प्रातः 09:30 बजे (महालक्ष्मी)
- मुख्यालय 'B' बनाम रतलाम – 04 जनवरी 2026, प्रातः 09:30 बजे (महालक्ष्मी)

नॉकआउट चरण

प्रथम सेमीफाइनल – 10 जनवरी 2026, प्रातः 09:30 बजे (ग्रुप 'A' विजेता बनाम ग्रुप 'B' उपविजेता)

द्वितीय सेमीफाइनल – 11 जनवरी 2026, प्रातः 09:30 बजे (ग्रुप 'B' विजेता बनाम ग्रुप 'A' उपविजेता)

फाइनल मुकाबला – 23 जनवरी 2026, प्रातः 10:00 बजे (महालक्ष्मी मैदान)

इस तरह की खेल प्रतियोगिताएँ अधिकारियों में स्वास्थ्य, उत्साह और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देती हैं। यह क्रिकेट टूर्नामेंट अधिकारियों में खेल भावना, टीमवर्क एवं आपसी समन्वय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे – भावनगर मण्डल

टीआरडी कार्य

नि.सू.सं. डीआरएम/ईएल/ईनि/बीवीपी/2025-26/01; दि. 19.12.2025; ई-टेंडर आमंत्रित करने के लिए सूचना; भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए मंडल रेल प्रबंधक (कर्षण वितरण), पश्चिम रेलवे, भावनगर परा द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए खुली निविदा आमंत्रित की जाती है:

निविदा संख्या: 09-TRDBVP-2025-26
कार्य का नाम: सनोसरा में अतिरिक्त लूप लाइन प्रदान करने के संबंधित टीआरडी कार्य.
अनुबंध मूल्य : ₹ 95,43,581.27/-; **टेंडर फीस:** NIL;
बयाना राशि : ₹ 1, 90, 900 /-
ऐड्रेस: डीआरएम (ट्रैक्शन) बीवीपी, डीआरएम कार्यालय, भावनगर परा-364003
निविदाकर्ताओ को अपनी निविदा ऑन लाईन लिंक **www.ireps.gov.in** पर जमा करना है. अधिक जानकारी के लिए वेबसाईट **www.ireps.gov.in** पर जाऐ.
ऑनलाईन निविदा भरने की अंतिम तिथि दिनांक 12.01.2026 को 15:00 बजे तक है.

हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly • हमें फोलो करें : x.com/WesternRly BVP-226

अटल नेतृत्व, अविरत विकास : सुशासन से महिला सशक्तिकरण

राज्य में लखपति दीदी तथा नमो ड्रोन दीदी योजना से महिलाएँ बनीं आत्मनिर्भर

▸▸ दो वर्ष में राज्य में लखपति दीदी की संख्या 5.96 लाख के पार, गाँव में रहने वालीं महिलाओं के सपने हो रहे हैं साकार

▸▸ कंकुबेन ने कच्छी हस्तकला उत्पादों की बिक्री से वार्षिक दस लाख रुपए से अधिक की कमाई की, अब ऑनलाइन साइट्स पर भी बिक्री

▸▸ प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गुजरात ने नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए अनेक सफल आयाम अपनाए हैं : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर : सुशासन द्वारा राज्य के नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य के साथ राज्य सरकार हमेशा प्रयासरत रही है। सुदूरवर्ती नागरिकों तक विकास पहुँचाने तथा महिलाओं को सशक्त बनाकर भारत की विकास यात्रा में जोड़ने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2023 में 'लखपति दीदी' योजना शुरू की गई थी। 2027 तक 3 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का इस योजना का उद्देश्य है। गुजरात की महिलाओं को इस योजना का व्यापक लाभ मिले; इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में व्यापक प्रयास किए गए हैं। परिणामस्वरूप दिसंबर 2025 तक राज्य में लगभग 5 लाख 96 हजार महिलाओं की आय एक लाख रुपए से अधिक तक पहुँची है और वे गर्व के साथ गुजरात की 'लखपति दीदी' बनी हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है, "प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गुजरात ने नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए अनेक सफल आयाम अपनाए हैं। लखपति दीदी योजना के सफल क्रियान्वयन से गुजरात आगामी समय में 10 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए तैयार है।"

कच्छ की कंकुबेन गर्वा की वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक

लखपति दीदी कार्यक्रम को राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक जमीनी स्तर पर क्रियान्वित किया है। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। कच्छ में भुज तहसील के मानकुवा गाँव में रहने वालीं कंकुबेन गर्वा का परिवार परंपरागत रूप से हस्तकला से जुड़ा हुआ है। उन्होंने 'सरस मेला' में शामिल होकर उनके कच्छी हस्तकला उत्पाद लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए। इसके बाद उन्होंने 1.5 लाख रुपए कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से तथा 4 लाख रुपए के क्रेडिट कैश लोन द्वारा गाँव में ही दुकान शुरू की और स्वयं-सहायता समूह की अन्य महिलाओं को जोड़कर उत्पादन बढ़ाना शुरू किया। आज उनके उत्पाद राज्य के बाहर भी पहुँचे हैं। वे एमेजोन जैसी विख्यात ऑनलाइन साइट्स पर भी बिक्री कर अपना व्यवसाय बढ़ा रही हैं। हाल में वे वार्षिक 10 लाख रुपए से अधिक आय अर्जित कर रही हैं और उनके कहे अनुसार उनकी इस सफलता में राज्य सरकार की ओर से लाइवलीहुड मिशन का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।

कैसे काम करती है लखपति दीदी योजना ?

यह योजना स्वयं-सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने में सहायक बनती है, जिससे उनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक हो सके। महिलाएँ कृषि, पशुपालन, हस्तकला तथा अन्य स्थानीय क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इसके लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता तथा बाजार से कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाती है, जिससे उनकी आय बढ़ सके। केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लखपति दीदी के लिए निम्न विवरण अनुसार आय की गणना की जाती है :

▸▸ कृषि एवं सम्बद्ध व्यवसाय की कुल वार्षिक आय।
▸▸ नॉन-फार्म एक्टिविटी जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज आदि की आय।
▸▸ परिवार में कोई व्यक्ति नौकरी करता हो, तो उसकी आय।
▸▸ फार्म तथा नॉन-फार्म व्यवसाय में मजदूरी कार्य से प्राप्त आय।
▸▸ सरकार के योजनागत लाभ द्वारा प्राप्त राशि।
▸▸ कमिशन, मानद् वेतन से प्राप्त आय।

नमो ड्रोन दीदी योजना से भावनाबेन को मिली नई पहचान

बनासकाँठा में काँकरेज तहसील के वरसाडा की निवासी भावनाबेन भरतकुमार चौधरी ने ड्रोन दीदी बनकर आसपास के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने बीए तक पढ़ाई की है और वे पशुपालन-खेती के व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत ड्रोन द्वारा कीटनाशक का छिड़काव करने के प्रशिक्षण के लिए उनका चयन होने के बाद वे काँकरेज तहसील में ड्रोन दीदी के रूप में जानी जाती हैं। वे गाँव में रहकर अपने सपने साकार कर रही हैं और आसपास की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरणा दे रही हैं। उल्लेखनीय है कि कक्षा 10 उत्तीर्ण न्यूनतम योग्यता के साथ 18 से 60 वर्ष आयु समूह की महिलाएँ नमो ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत ड्रोन पायलट बन सकती हैं।

248 मास्टर ट्रेनर्स द्वारा 10 हजार से अधिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को प्रशिक्षण

इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गुजरात सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तहसील स्तर पर 248 मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति की गई है, जिन्होंने अब तक 10 हजार से अधिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स को प्रशिक्षण दिया है। ये कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स स्वयं-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सहयोग देंगे। इस समग्र प्रक्रिया के लिए डिजिटल आजीविका रजिस्टर पर डेटा अपडेट किया जाता है, जो देखरेख के साथ महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग एवं मार्केट कनेक्टिविटी देने में सहायक होता है।

राज्य में 10 लाख से अधिक संभावित लखपति दीदी की पहचान

राज्य के प्रशिक्षित कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) द्वारा हाल में 10.74 लाख महिलाओं की पहचान की गई है, जो लखपति दीदी बन सकती हैं। चिह्नित की गईं संभावित लखपति दीदी की मौजूदा गतिविधियों तथा उनके पास उपलब्ध स्रोतों, हुए खर्च और आय का विवरण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल आजीविका रजिस्टर तैयार किया गया है। इस रजिस्टर से प्राप्त जानकारी के आधार पर चिह्नित की गईं लखपति दीदी को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण, एसेट, आर्थिक सहायता तथा मार्केटिंग के लिए आवश्यक सपोर्ट किया जा रहा है।

घने कोहरे की मार से हवाई यातायात बेहाल, IndiGo की चार उड़ानें जयपुर डायवर्ट, यात्रियों को घंटों तक झेलनी पड़ी परेशानी

जयपुर/चंडीगढ़। उत्तर भारत में मौसम के बदले मिजाज और घने कोहरे ने हवाई यातायात की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। शुक्रवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर दृश्यता बेहद कम रहने के कारण IndiGo एयरलाइंस की कई उड़ानों को अंतिम समय पर जयपुर डायवर्ट करना पड़ा, जिससे सैकड़ों यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। चंडीगढ़ आने वाली अब तक चार उड़ानों को जयपुर भेजा जा चुका है, जबकि रात में भी कोहरे में राहत की संभावना कम बताई जा रही है, ऐसे में इन विमानों के दोबारा चंडीगढ़ रवाना होने को लेकर असमंजस बना हुआ है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को खराब मौसम और घने कोहरे की वजह से अहमदाबाद से चंडीगढ़ जा रही IndiGo की फ्लाइट 6E-6506, जयपुर से चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट 6E-7414 और हैदराबाद से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई फ्लाइट 6E-6252 को जयपुर डायवर्ट कर दिया गया। इसके बाद बेंगलुरु से चंडीगढ़ जा रही IndiGo की एक और फ्लाइट 6E-6385 को भी अंतिम समय पर जयपुर भेजना पड़ा। अचानक हुए इन डायवर्जन के चलते यात्रियों को जयपुर एयरपोर्ट पर विमानों के भीतर ही काफी देर तक बैठाए रखा गया, जिससे नाराजगी और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, चंडीगढ़ में शाम और रात के समय कोहरे की स्थिति में सुधार की संभावना बेहद कम है। इसी कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि डायवर्ट की गई उड़ानें कब और कैसे चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगी। इस अनिश्चितता ने यात्रियों की परेशानी और बढ़ा दी, जिनमें कई ऐसे भी थे जिन्हें आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट्स या जरूरी कार्यक्रमों के लिए समय पर पहुंचना था।

इससे एक दिन पहले गुरुवार को भी हवाई सेवाएं प्रभावित रहीं। IndiGo की जयपुर से चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट 6E-7742, जो सुबह 5 बजकर 50 मिनट पर उड़ान भरने वाली थी, पहले करीब ढाई घंटे तक देरी का शिकार हुई और बाद में एयरलाइन ने ऑपरेशनल कारणों का हवाला देते हुए इसे पूरी तरह रद्द कर दिया। सूत्रों के अनुसार, विमान की उपलब्धता नहीं होने के चलते यह फैसला लिया गया, जिससे यात्रियों को आखिरी वक्त पर वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश करनी पड़ी।

इसी तरह एयर इंडिया की दिल्ली से सुबह 7 बजकर 10 मिनट पर जयपुर आने वाली फ्लाइट AI-1767 को भी अंतिम समय पर रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही जयपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट AI-1834 को भी कैंसिल कर दिया गया। एयर इंडिया से जुड़े सूत्रों ने बताया कि दिल्ली से आने वाली फ्लाइट को ऑपरेशनल कारणों से उड़ान की अनुमति नहीं मिल सकी, जबकि जयपुर से दिल्ली जाने वाली उड़ान को विमान की कमी के चलते रद्द करना पड़ा। लगातार हो रही उड़ानों की देरी, डायवर्जन और रद्द होने की घटनाओं से यात्रियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है।

हिजाब प्रकरण से सुलगा सियासी और सामाजिक आक्रोश, रांची में फूंका गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला

रांची। बिहार में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से एक महिला डॉक्टर से हिजाब हटवाने के प्रकरण ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखा विवाद खड़ा कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर बिहार से लेकर झारखंड तक विरोध की लहर फैल गई है। शुक्रवार को झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड मुस्लिम युवा मंच के बैनर तले बड़ी संख्या में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शन के दौरान "महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान" जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा।

यह प्रदर्शन झारखंड मुस्लिम युवा मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद अय्यूबी के नेतृत्व में किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा किसी महिला, खासकर एक डॉक्टर जैसे सम्मानित पेशे से जुड़ी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार न केवल निंदनीय है, बल्कि यह संविधान में निहित समानता, स्वतंत्रता और सम्मान के अधिकारों का भी खुला उल्लंघन है। उनका कहना था कि यह मामला सिर्फ एक महिला या एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज और लोकतांत्रिक व्यवस्था की गरिमा से जुड़ा हुआ है।

मोहम्मद शाहिद अय्यूबी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ऐसा देश है जहां नारी को शक्ति, सम्मान और संवेदना का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में नारी को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का रूप माना गया है, वहीं इस्लाम में मां के कदमों तले जन्नत और बेटी को जिगर का टुकड़ा कहा गया है। ऐसे देश में किसी महिला के पहनावे पर सवाल उठाना या उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करना बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब देश की बेटियां शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़कर देश का नाम रोशन कर रही हैं, तब उनके साथ इस तरह का व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यह घटना पद की गरिमा और संवैधानिक मर्यादाओं की अनदेखी का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपनी भाषा और आचरण में संयम नहीं बरतता, तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है।

चोरी ही पेशा, गांव से विदेश तक फैला नेटवर्क: झारखंड के मोबाइल चोर गिरोह का सनसनीखेज खुलासा

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सामने आया एक मामला न सिर्फ पुलिस को चौंकाने वाला है, बल्कि देश में संगठित अपराध के नए और खतरनाक स्वरूप को भी उजागर करता है। जयपुर पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसकी जड़ें झारखंड के साहेबगंज जिले के एक गांव से जुड़ी हैं और जिसकी पहुंच भारत से बाहर बांग्लादेश तक फैली हुई है। इस गिरोह से जुड़े आरोपियों ने पूछताछ में जो खुलासे किए हैं, उन्होंने कानून व्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग के मामलों में झारखंड के साहेबगंज जिले के तालझारी थाना क्षेत्र के रहने वाले सूरज महतो और सेख सोबराती को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से 31 महंगे मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 22 लाख रुपये बताई जा रही है। ये सभी मोबाइल जयपुर और अन्य शहरों से चोरी किए गए थे। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे किसी छोटे-मोटे

गिरोह का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे संगठित नेटवर्क से जुड़े हैं, जहां चोरी को बाकायदा पेशे के रूप में अपनाया गया है।

सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह रहा कि आरोपियों ने बताया कि उनके गांव में चोरी ही लोगों की मुख्य आजीविका है। उनका कहना है कि यह काम किसी एक-दो व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे गांव का जीवनयापन मोबाइल चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर निर्भर है। बच्चों से लेकर युवाओं तक को कम उम्र में ही इस रास्ते पर डाल दिया जाता है। चोरी को वहां अपराध नहीं, बल्कि एक कौशल की तरह देखा जाता है, जिसे सीखना और सिखाना सामान्य बात मानी जाती है।

आरोपियों ने यह भी बताया कि मोबाइल चोरी करने से पहले उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। किस भीड़ में कैसे मोबाइल निकालना है, पुलिस और सीसीटीवी से कैसे बचना है, चोरी के बाद माल को सुरक्षित तरीके से कैसे बाहर पहुंचाना है—इन सबकी विस्तृत जानकारी दी जाती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद गैंग के सदस्य देश के अलग-अलग शहरों में भेजे जाते हैं, जहां वे भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाजारों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक आयोजनों में मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते हैं।

इस गिरोह की कार्यप्रणाली यहीं खत्म नहीं होती। पूछताछ में यह भी सामने आया कि चोरी किए गए मोबाइल फोन को पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भेजा जाता है। वहां इन मोबाइलों को बेच दिया जाता है या उनके पुर्जे अलग-अलग कर दिए जाते हैं, जिससे उनकी पहचान करना लगभग असंभव हो जाता है। इसी बांग्लादेश कनेक्शन के चलते यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय अपराध के दायरे में भी आ जाता है।

इससे पहले भी झारखंड के साहेबगंज जिले में इसी तरह के एक अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा हो चुका है। उस मामले में पुलिस ने पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले विजय मंडल, सुरेंद्र नोनिया और सिटून मंडल को गिरफ्तार किया था। उनके पास से झारखंड सहित कई अन्य राज्यों से चोरी किए गए अलग-अलग कंपनियों के करीब 71 मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। तब भी पूछताछ में यह बात सामने आई थी कि चोरी के बाद मोबाइल फोन बांग्लादेश भेजे जाते थे।

जयपुर पुलिस का मानना है कि यह गिरोह सिर्फ एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। पुलिस अब झारखंड और पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ मिलकर इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। इस मामले ने यह साफ कर दिया है कि जब अपराध को सामाजिक स्वीकार्यता और आजीविका का रूप दे दिया जाता है, तो वह सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं, बल्कि समाज के भविष्य के लिए भी एक गंभीर खतरा बन जाता है।

असम फतह की तैयारी में उतरी भाजपा, चुनावी बिगुल के साथ पीएम मोदी ने की कोर रणनीति बैठक

गुवाहाटी। असम में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुवाहाटी पहुंचकर न सिर्फ जनसभा और रोड शो के जरिए सियासी माहौल को गरमाया, बल्कि पार्टी संगठन के साथ एक अहम रणनीतिक बैठक कर चुनावी तैयारियों की दिशा भी तय की। यह बैठक भाजपा के राज्य मुख्यालय वाजपेयी भवन, बासिष्ठा में हुई, जिसे आगामी चुनावों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

करीब एक घंटे तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने असम भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और संगठन पदाधिकारियों के साथ सीधे संवाद किया। पीएम मोदी ने नेताओं से सरकार की जमीनी छवि, जनकल्याणकारी योजनाओं के असर और संगठन की मजबूती को लेकर विस्तार से जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने यह जानने की कोशिश की कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं आम जनता तक किस हद तक पहुंच रही हैं और किन क्षेत्रों में और अधिक मेहनत की जरूरत है।

बैठक की खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी किसी मंच पर नहीं बैठे, बल्कि सभी नेताओं के बीच साधारण कुर्सी पर बैठकर बातचीत करते नजर आए। नेताओं के अनुसार, यह औपचारिक बैठक से ज्यादा एक खुला संवाद था, जिसमें पीएम मोदी एक वरिष्ठ मार्गदर्शक की भूमिका में दिखे। उन्होंने कई वरिष्ठ नेताओं की कुशलक्षेम पूछी और पुराने कार्यकर्ताओं के योगदान को भी याद किया। पूर्व राज्य भाजपा अध्यक्ष नारायण बोरकोटकी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसी शीर्ष नेता की तरह नहीं, बल्कि पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह चर्चा कर रहे थे, जिससे सभी नेता सहज महसूस कर रहे थे।

बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी के सारुसजई इलाके से करीब 3.8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रोड शो के दौरान सड़कों के दोनों ओर भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी और भाजपा समर्थकों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वे सीधे वाजपेयी भवन पहुंचे, जहां यह महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि यह पहली बार है जब देश के किसी प्रधानमंत्री ने सीधे राज्य भाजपा मुख्यालय का दौरा किया है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में करीब 280 नेता मौजूद थे, जिनमें वर्तमान और पूर्व सांसद, मंत्री, विधायक और पूर्व राज्य अध्यक्ष शामिल थे। सैकिया के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, युवाओं और महिलाओं को जोड़ने तथा विकास कार्यों को चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाने पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा केवल पार्टी बैठक तक सीमित नहीं रहा। अपने दो दिवसीय असम प्रवास के दौरान उन्होंने राज्य के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बर्दोलोई की प्रतिमा का अनावरण किया और गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया और असम के विकास को भाजपा की प्राथमिकता बताया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह रणनीतिक बैठक और पीएम मोदी की सक्रियता साफ संकेत है कि भाजपा असम चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा है, बल्कि यह संदेश भी दे दिया है कि आने वाले महीनों में असम की राजनीति पूरी तरह चुनावी मोड में रहने वाली है।

सप्ताह के दौरान सोना वायदा में 2052 रुपये और चांदी वायदा में 4623 रुपये का ऊछाल: क्रूड ऑयल वायदा 85 रुपये फिसला

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 12 से 18 दिसंबर के सप्ताह के दौरान कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस, इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 3413665.58 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 459713.24 करोड़ रुपये का साप्ताहिक कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 2953864.13 करोड़ रुपये का साप्ताहिक नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिसंबर वायदा 33065 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में सप्ताह के दौरान कुल प्रीमियम टर्नओवर 42095.17 करोड़ रुपये का हुआ।

आलोच्य अवधि के सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 377216.12 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 132442 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 135590 रुपये के उच्च और 132275 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 132469 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 2052 रुपये या 1.55 फीसदी की तेजी के संग 134521 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा सप्ताह के अंत में 1899 रुपये या 1.8 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 107605 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा सप्ताह के अंत में 203 रुपये या 1.53 फीसदी की तेजी के संग 13442 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी जनवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 130905 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 133633 रुपये के उच्च और 130400 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 1779 रुपये या 1.36 फीसदी की मजबूती के साथ 132684 रुपये प्रति 10 ग्राम बंद हुआ। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम सप्ताह के आरंभ में 131334 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 133870 रुपये के उच्च और 130681 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 131137 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 1818 रुपये या 1.39 फीसदी की बढ़त के साथ 132955 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सप्ताह के आरंभ में 196958 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 207833 रुपये और नीचे में 190077 रुपये पर पहुंचकर, 198942 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 4623 रुपये या 2.32 फीसदी ऊछलकर 203565 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 5054 रुपये या 2.54 फीसदी की तेजी के संग 204264 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 5046 रुपये या 2.53 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट सप्ताह के अंत में 204269 रुपये प्रति किलो पर आ गया। मेटल वर्ग में 35491.31 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा 15 पैसे या 0.01 फीसदी की नरमी के साथ 1111.7 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 17.65 रुपये या 5.51 फीसदी लुढ़ककर 302.45 रुपये प्रति किलो बंद हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम दिसंबर वायदा 1.5 रुपये या 0.53 फीसदी बढ़कर 282.2 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। जबकि सीसा दिसंबर वायदा 50 पैसे या 0.27 फीसदी घटकर 181.4 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 459713.24 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 2953864.13 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ साप्ताहिक टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 377216.12 करोड़ रुपये का हुआ साप्ताहिक कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 33065 पॉइंट के स्तर पर

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 46955.54 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 5277 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 5277 रुपये और नीचे में 5038 रुपये पर पहुंचकर, 85 रुपये या 1.63 फीसदी गिरकर 5114 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा 87 रुपये या 1.67 फीसदी की गिरावट के साथ 5116 रुपये प्रति बैरल के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा नैचुरल गैस दिसंबर वायदा 380.9 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 386.2 रुपये और नीचे में 350.8 रुपये पर पहुंचकर, 381.1 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 24.9 रुपये या 6.53 फीसदी गिरकर 356.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी दिसंबर वायदा 25 रुपये या 6.56 फीसदी लुढ़ककर 356.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बंद हुआ।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा 909.5 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 33.9 रुपये या 3.72 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 944.9 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सप्ताह के दौरान सोना के विभिन्न अनुबंधों में 187732.01 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 189484.11 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 28257.61 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 2181.02 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 230.74 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 4821.93 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 8760.12 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 38126.92 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

सप्ताह के अंत में ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 14316 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 43496 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 6203 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 90580 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 9444 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 12888 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 29432 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 57672 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 21437 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 16132 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स दिसंबर वायदा सप्ताह के आरंभ में 32632 पॉइंट पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 33370 के उच्च और 32086 के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 502 पॉइंट बढ़कर 33065 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ।